



गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष, दोनों सदन दिनभर के लिए स्थगित

नयी दिल्ली ३१/०७
(संवाददाता): संसद में
शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों ने
प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की
कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री
अमित शाह के इस्तीफे की मांग
करते हुए हंगामा किया जिसके
कारण दोनों सदनों की
कार्यवाही दिन भर के लिए
स्थगित कर दी गई। हंगामे के
बीच ही लोकसभा ने जन्म और
मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून
में संशोधन के प्रावधान वाले
विधेयक को बिना चर्चा के
पासित कर दिया। निचले सदन
की बैठक शुरू होते ही विपक्षी
सदस्यों ने छात्रों पर पुलिस की
कार्रवाई को लेकर हंगामा शुरू
कर दिया। वे आसन के निकट
पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह
के इस्तीफे की मांग करने लगे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
ने विपक्षी सदस्यों से अपने
स्थान पर जाने और प्रश्नकाल

चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा, “कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, यह सदस्यों का समय है।

आज प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिये। आप सदन को चलने दें।” उन्होंने कहा, “आज प्रियंका (गांधी) जी का भी प्रश्न होना है और वह प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं।” बिरला ने कहा, “कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल-बदलकर आते हैं उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे

है।" सदन में निर्दलीय सदस्य राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवको आज साधुओं की तरह भगवा वस्त्र पहने हुए देखा गया। शरीर-शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। इसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण अब तक प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। उधर राज्यसभा में भी समान नजारा दिखा। नीट प्रश्नपत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस



कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामे किया। इस वजह से राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब बीस मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च

सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल चार सदस्य ही लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठा सके। पूर्वाह्न 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सी पी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद विपक्षी

सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया।

हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति से अनुमति मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में

विपक्ष के नेता खरगे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया इस पर खरगे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वहाँ पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं खरगे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने नोटिस पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह

मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इसीफे की भी मांग की है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर “सड़क-छाप (ओछी) राजनीति” करने और “सदन की गरिमा से खिलवाड़” करने का आरोप लगाया। चौहान ने कहा, “वे सड़क-छाप राजनीति कर रहे हैं और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहे हैं। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है... वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं।” उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन अपनी बात का असर होते न देख उन्होंने 11 बज कर बीस मिनट पर कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

जयशंकर ने ईरान से वाणिज्यिक जहाजों पर हमले रोकने का किया आग्रह

नयी दिल्ली ३१/०७ (संवाददाता): भारत ने शुक्रवार को ईरान से दृढ़ता के साथ अपील की कि वह किसी भी हालत में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले नहीं करे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष अज्जास अराघची से फोन पर हुई बातचीत के दौरान कहा कि भारत किसी भी पक्ष की ओर से किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "क्षेत्र में जारी संघर्ष को लेकर अराघची से बातचीत में अपनी गहरी चिंता जाहिर की। इतिहास मैंने जोर देकर कहा कि किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों से बचा जाना चाहिए।" उन्होंने कहा, "भारत किसी भी पक्ष की ओर से किए गए ऐसे हमले की निंदा करता है।" जयशंकर ने कहा कि अराघची ने उन्हें मौजूदा



घटनाक्रम और जारी वार्ताओं पर ईरान के दृष्टिकोण से अवगत कराया। उन्होंने कहा, “भारत हमेशा संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है।” दोनों विदेश मंत्रियों के बीच यह बातचीत ऐसे समय हुई है, जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। भारत होमुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर लगातार गंभीर चिंता जताता रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बह्यस्तिवार को राज्यासभा में बताया कि फरवरी से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में 10

नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 75 अन्य घायल हुए हैं। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंह ने कहा, “2026 में पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। इनमें से एक सऊदी अरब, दो कुवैत, आठ ओमान, एक इराक और चार संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में मारे गए। वहीं, 75 भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें 32 संयुक्त अरब अमीरात, 24 ओमान, चार कातर, 13 कुवैत, एक सऊदी अरब और एक इजराइल में घायल हुआ।

नयी दिल्ली ३१/०७
(स्वादादता): उच्चतम
न्यायालय ने शुक्रवार को कहा
कि अगर पति व्यभिचार का
आरोप लगाता है, तो अदालत
को पत्नी को अंतर्निगम भञ्ज
देने का फैसला सुनाने से पहले
पहले उस आरोप पर निर्णय लेना
होगा। न्यायमूर्ति संजय करोल
और न्यायमूर्ति विपुल एम
पंचोली की पीठ ने कहा कि
अदालतों का यह मानना गृष्टिपूर्ण
होगा कि ऐसे आरोप पर निर्णय
केवल सुनवाई के अंतिम चरण
में ही किया जा सकता है। पीठ
ने कहा, “चूँकि, दंड प्रक्रिया
संहिता (सीआरपीसी) की धारा
125(4) में यह प्रावधान है कि
अगर व्यभिचार का आरोप
साबित हो जाता है, तो पत्नी
को अंतर्निगम और न ही अंतिम
गुजारा-भञ्ज की हकदार होगी।

इसलिए हमारा मत है कि अगर पति धारा 125(4) के तहत आवेदन करता है और शुरू में ही सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप साबित कर देता है, तो अंतरिम गुजारा-भत्ता पर



रोक लगाई जा सकती है।”
 शीर्ष अदालत का यह फैसला
 एक व्यक्ति की अपील पर
 आया है। व्याभिचार के आधार
 पर गुजरात भ्रमा का विरोध करने
 वाली व्यक्ति की याचिका को
 राजस्थान उच्च न्यायालय ने
 खारिज कर दिया, जिसे चुनौती
 देते हुए उसने शीर्ष अदालत
 का रुख किया था।
 याचिकाकर्ता व्यक्ति और
 महिला का विवाह सात जुलाई
 2014 को हुआ था।

शादी के कुछ साल बाद ही उनके बीच परेशानियां शुरू हो गईं, जिसके कारण महिला ने कथित तौर पर पुरुष पर कई आरोप लगाए और पुलिस में शिकायतें भी दर्ज कराईं। आखिरकार, 13 मई 2020 को उसने अपने बच्चे और कीमती सामान के साथ ससुराल छोड़ दी।

भोजशाला परिसर के पास उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बाद कड़ी सुरक्षा में नमाज अदा

भोजशाला ३१/०७
(संवाददाता): उच्चतम
न्यायालय की अनुमति के एक
दिन बाद, मध्यप्रदेश के धर्म
जिले में मौलाना भोजशाला-
कमाल मौलिया परिसर के निकट
शुक्रवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा
के बीच मुस्लिम समुदाय ने
निर्धारित स्थल पर नमाज अदा
की। जिला प्रशासन ने बताया
कि मुस्लिम समुदाय के
प्रतिनिधियों के साथ बैठक के
बाद भोजशाला के निकट सर्वे
नंबर 612 को नमाज के लिए
चुना गया था। मध्यप्रदेश उच्च
न्यायालय द्वारा मई में
भोजशाला-कमाल मौलिया परिसर
को देवी सरस्वती का मंदिर
घोषित किए जाने के बाद पहली
बार बड़ी संख्या में मुस्लिम जुमे
की नमाज के लिए पहुंचे।

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि मुस्लिम समुदाय को विवादित भोजशाला परिसर से सटे दरगाह परिसर में शुक्रवार को दोपहर एक बजे से तीन बजे के बीच नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए।



अदालत के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने नमाज के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ कीं। अधिकारियों ने बताया कि दोपहर करीब ढाई बजे 150 से अधिक लोग नमाज के लिए पहुंचे।

बारिश के बावजूद उन्होंने निर्धारित स्थल पर नमाज अदा की। उन्होंने बताया कि नमाज से पहले जिला प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। सुरक्षा के मद्देनजर भोजशाला परिसर के चारों ओर अवरोधक लगाए गए और परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।

मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य अजुल समद ने कहा, हमने अपनी मांगें उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखीं। अदालत ने गंभीरता से सुनवाई करते हुए कमाल मौला मस्जिद से लगे क्षेत्र में नमाज अदा करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अदालत ने सर्वे नंबर 611, 612 और 596 का उल्लेख किया था तथा उपलब्ध स्थान पर नमाज की व्यवस्था करने को कहा है।

समद ने कहा, प्रशासन के सहयोग से हमने सर्वे नंबर 612 पर नमाज अदा की और सर्वे नंबर 611 छोड़ दिया, ताकि

किसी की भावनाओं या आस्था को ठेस न पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डायर ने कहा, बृहस्पतिवार शाम से ही मुस्लिम समुदाय के साथ लगातार संवाद किया गया। प्रशासन और पुलिस विभाग ने आपसी सहमति से आज शांतिपूर्ण ढंग से उसी स्थान पर नमाज कराने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि नमाज

के दौरान लगभग 800 से 900 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इनमें विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के जवान भी शामिल थे। शहर के संवेदनशील इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी की गई।

उपखंड अधिकारी (एसडीएम) राजकुमार हलधर ने कहा कि प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं के बीच करीब 150 लोगों ने सर्वे नंबर 612 पर शांतिपूर्वक नमाज अदा की। इससे पहले धार के जिलाधिकारी राजीव रंजन मीणा ने बताया था कि नमाज के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक

व्यवस्थाएं की गई हैं। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मई में अपने फैसले में भोजशाला-कमाल मौला परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर माना था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वर्ष 2003 के उस आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को परिसर में शुक्रवार की नमाज की अनुमति दी गई थी।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने 242 पत्रों के फैसले में कहा था कि 11वीं शताब्दी के इस स्मारक का धार्मिक स्वरूप वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर स्थापित हो चुका है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि मुस्लिम पक्ष मस्जिद निर्माण के लिए जिले में अलग भूमि आवंटित करने का अनुरोध राज्य सरकार से कर सकता है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसने बृहस्पतिवार को निर्वाचित परिसर से सटे दरगाह परिसर में शुक्रवार की नमाज की अनुमति दी।



पाकिस्तान पर भारत का अब तक का सबसे बड़ा हमला, विदेश मंत्रालय ने दुनिया के सामने खोली आतंकिस्तान की पूरी पोल

नयी दिल्ली ३१/०७ (संवाददाता): भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में आम नागरिकों पर हो रहे दमन को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ बेहद तीखा और आक्रामक रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस वार्ता में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वहां की सजा अपने ही नागरिकों के खिलाफ बर्बर बल प्रयोग कर रही है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर जिस तरह बल प्रयोग किया गया है, उसमें अब तक 40 से अधिक निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सजा का स्थानीय जनता के प्रति तिरस्कार उस समय पूरी दुनिया के सामने

उजागर हो गया, जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को ही दुश्मन करार दे दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति को लेकर भी बड़ा राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के विशेष सहायक स्वयं यह स्वीकार कर चुके हैं कि जिन मुजाहिदीनों को पाकिस्तान की सजा ने वर्षों तक प्रशिक्षित किया, धन उपलब्ध कराया, हथियार दिए और भारत में आतंक फैलाने के लिए भेजा, वही अब पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं। भारत ने इसे पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक नीति की सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति बताते हुए कहा कि आतंकवाद का जिस ढांचे को पाकिस्तान ने खड़ा किया था, अब वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है।

रणधीर जायसवाल ने पीओजेके में तथाकथित चुनावों का भी उल्लेख करते हुए कहा

कि वे पाकिस्तान की सजा व्यवस्था के लिए एक अपमानजनक अस्वीकृति साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीओजेके के लोगों ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से गैरकानूनी हथ्याओं की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की कार्रवाई की निष्पक्ष जांच करने और उसे उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराने की अपील भी की। साथ ही भूटान के साथ विकास सहयोग को लेकर प्रभासाक्षी के प्रश्न के उजर में विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश सचिव की हालिया भूटान यात्रा भारत-भूटान विकास सहयोग मंच (डुटुलद्रडु-क़द्रहहडुठु छ़द्र1द्रद्यशश्चद्रद्रडुह् छ़शश्चद्रहडुह्डुह्द्रथडु क़्यडुह्-द्रथहद्र) के तहत हुई थी। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय विकास साझेदारी की व्यापक समीक्षा की और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया। विदेश मंत्रालय



ने कहा कि यात्रा के दौरान दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पहला समझौता भूटान के लिए लाइन ऑफ़ क्रेडिट (ऋण सहायता) से संबंधित था, जबकि दूसरा समझौता अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एज्स) और भूटान के खेसर ग्यालपो अस्पताल के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया। दोनों पक्षों ने भविष्य की विकास परियोजनाओं और नई पहलों पर भी चर्चा की। भारत ने दोहराया कि भूटान उसकी ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति का प्रमुख साझेदार है और दोनों देशों के बीच विकास, आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग लगातार और अधिक मजबूत हो रहा है। इसके अलावा, एक अन्य प्रश्न के उजर में समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय नौवहन के मुद्दे पर भारत ने अपने स्थापित रुख को दोहराया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत हमेशा अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर निर्बाध और स्वतंत्र नौवहन का समर्थक रहा है तथा वैश्विक समुद्री व्यापार की सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। साथ ही नेपाल के साथ संबंधों पर पूछे गए प्रश्न के उजर में रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच

कई द्विपक्षीय मुद्दे एजेंडे में शामिल हैं और इन पर तकनीकी स्तर सहित विभिन्न संस्थागत तंत्रों के माध्यम से नियमित बातचीत जारी रहती है। उन्होंने संकेत दिया कि भारत-नेपाल संबंध निरंतर संवाद और सहयोग के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं।

रूसी सेना में भर्ती भारतीय नागरिकों के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक भारत के प्रयासों से 139 भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित की जा चुकी है। हालांकि अभी भी लगभग दो दर्जन भारतीय नागरिकों के रूस में होने की सूचना है, जिनकी वापसी के लिए रूस के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा गया है। मंत्रालय ने एक बार फिर युवाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि वे संदिग्ध एजेंसियों और जोखिमपूर्ण विदेशी नौकरी के प्रस्तावों से सतर्क रहें। इसके अलावा, अमेरिकी सीनेट में पेश एक विधेयक से जुड़े प्रश्न पर भारत

ने संयमित लेकिन स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित है और देश अपने नागरिकों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध स्रोतों से आपूर्ति सुनिश्चित करता रहेगा। जायसवाल ने बताया कि इस विषय पर अमेरिका के विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद जारी है।

ब्रिजस शिखर सच्मेलन को लेकर भारत ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष वह संगठन की अध्यक्षता कर रहा है और भारत में शिखर सच्मेलन आयोजित करने की व्यापक तैयारियां चल रही हैं। निमंत्रण और अन्य तकनीकी पहलुओं पर उचित समय पर जानकारी साझा की जाएगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के पास रणनीतिक व्यापार नियंत्रण के

लिए मजबूत कानूनी और नियामकीय व्यवस्था मौजूद है। उन्होंने कहा कि दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों का निर्यात पूरी तरह राष्ट्रीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप किया जाता है।

इसके अलावा, यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना होने के बाद हमले का शिकार बने जहाज एमवी एजीएन रैग्नार पर मौजूद भारतीय नागरिकों की स्थिति पर विदेश मंत्रालय ने बताया कि चार भारतीय चालक दल के सदस्य जहाज पर थे। इनमें दो सुरक्षित हैं, जबकि दो अब भी लापता हैं। यूक्रेन और रोमानिया, दोनों पक्षों की ओर से खोज एवं बचाव अभियान चलाया गया है। भारत दोनों देशों के संपर्क में है और लापता भारतीयों के परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा, अमेरिका से भारतीय नागरिकों के निर्वासन के आंकड़े भी विदेश मंत्रालय ने साझा किए।

झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बोले- छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित है सरकार

नयी दिल्ली ३१/०७ (संवाददाता): झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुक्रवार को कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित है और राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए जा रहे हैं। राज्यपाल के रूप में अपने दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम से इतर मीडिया से बात करते हुए गंगवार ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों को उसी तरह से सुलझाया जाना चाहिए जैसे केंद्र सरकार ने दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को संभाला था। झारखंड में जारी छात्रों के प्रदर्शनों से जुड़े एक सवाल के जवाब में गंगवार ने कहा, “आपने देखा कि दिल्ली में भी विरोध-प्रदर्शन हुआ था। वहां



मामले को सुलझा लिया गया। यहां भी इसे उसी तरह सुलझाया जाना चाहिए।” राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित धांधली व अनियमितताओं को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हर राज्य को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अनियमितताएं होती हैं।हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य प्रभावित न हो।” उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र

में सुधारों को एक “नयी दिशा” देनी चाहिए। गंगवार ने यह भी कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।

इससे पहले, राज्यपाल के रूप में दो वर्ष पूरे होने पर लोक भवन में कुलपतियों, शिक्षाविदों, संपादकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से बातचीत करते हुए गंगवार ने दोहराया कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में उच्च शिक्षा को मजबूत करना उनकी

प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहा है।

अपने कार्यकाल को याद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने अपने लंबे संसदीय करियर की तरह ही पूरी प्रतिबद्धता के साथ सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। राज्यपाल ने राज्य के हितों से जुड़े मुद्दों पर सहयोग देने के लिए राज्य सरकार का भी आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि ऐसा रचनात्मक सहयोग जन कल्याण और विकास पहलों को मजबूत करता रहेगा। इस अवसर पर एक कॉफी-टेबल बुक “संवाद से विश्वास” का भी विमोचन किया गया, जिसमें राज्यपाल के दो साल के कार्यकाल के दौरान की गई पहलों, उपलब्धियों और जनसंपर्क का दस्तावेजीकरण किया गया है।

सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार का चहुंमुखी विकास , सहयोग शिविर से मिला त्वरित समाधान

पटना ३१/०७ (संवाददाता): सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहैल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की दूरदर्शी सोच के अनुरूप आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य के सभी पंचायतों, प्रखंडों और नगर निकायों में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 19 मई 2026 से शुरू इस शिविर के तहत लोगों की समस्याओं से संबंधित 5 लाख 83 हजार 8 सौ 66 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 5 लाख 33 हजार 904 मामलों का समय सीमा के भीतर निपटारा किया जा चुका है। शेष लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया भी तेजी से की जा रही है। विदित है कि सहयोग शिविर के सबसे ज्यादा मामले भोजपुर, पश्चिम चम्पारण, पटना, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में प्रतिवेदित किए गए। सोहैल ने यह भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट



चौधरी जी के नेतृत्व में राज्य के सर्वांगीण विकास और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में लगातार कार्य किये जा रहे हैं। इस क्रम में राज्य में सहयोग शिविर का आयोजन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से सहयोग पोर्टल का निर्माण कराया गया है, जिस पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कराया जा सकता है। साथ ही, निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 डायल कर सहयोग शिविर से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

विगत समय में सामान्य प्रशासन विभाग की कई उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री सोहैल ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग;

किया जा चुका है। इस व्यवस्था को अधिक दक्ष बनाने के उद्देश्य से दिनांक 23 जून 2026 से तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों की स्वतः अपील की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत अब तक कुल 6934 अपील के मामलों में 5503 मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से हर प्रमंडल में एक लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और जिले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके तहत प्राप्त आवेदनों में 19.38 लाख से अधिक परिवारों का निपटारा

किया जा चुका है। प्रेस वार्ता के दौरान सोहैल ने सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली, सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मियों का क्षमतावर्धन, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, युवाओं को उपलब्ध कराए गए रोजगार, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, चल-अचल संपत्ति विवरण, हेल्पलाइन एवं कॉल सेंटर से संबंधित योजनाओं के साथ ही महत्वपूर्ण प्रशानिक निर्णयों से अवगत कराया। इस अवसर पर विशेष सचिव संजय कुमार, बीपीएसएम के अपर मिशन निदेशक मो. राशिद कलीम अंसारी, संयुक्त सचिव मो. आफाक अहमद आदि लोगों की प्रमुख उपस्थिति रही।

कलिंग समाचार

THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)

PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com



विविध समाचार



आप भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस से चार कदम आगे : नायब सैनी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जनता से जो वायदें किए थे वह 4 साल बीत जाने के बाद भी पूरे नहीं हुए हैं। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है तथा आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस से भी चार कदम आगे है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को लुधियाना स्थित छत पूजा मैदान में आयोजित पूर्वांचल सम्मान रैली को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री का यहां पहुंचने पर पदाधिकारियों ने भव्य अभिनन्दन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर पूर्वांचल सम्मान रैली के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि लुधियाना एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगरी है और इस मेहनतकश धरती को मैं शीश नवा कर नमन करता हूं। पंजाब गुरुओं की, पीरों की और वीरों की भूमि है। लुधियाना की इस ऐतिहासिक धरती पर, जिसे पंजाब की औद्योगिक राजधानी और भारत का 'मैनचेस्टर' भी कहा जाता है, मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सब का वंदन करता हूं। यह रैली केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि परिवर्तन का संदेश है। पंजाब भारत की आत्मा है। यह सीमाओं का प्रहरी है, खेतों की खुशबू है, ढोल की थाप है, गुरुओं की वाणी है और शौर्य की पहचान है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर



कांग्रेस पार्टी व आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस से भी चार कदम आगे है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनानी है। लोग कांग्रेस और आप को बाहर करने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आम आदमी पार्टी ने चार साल में कुछ नहीं किया। लोगों से झूठ बोला, झूठे सब्जबाज दिखाए। एक भी वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। इतना ही नहीं केजरीवाल व उसके नेता अपने आपको कटर ईमानदारी कहते थे उनका असली चेहरा सारे देश के सामने आया है। केजरीवाल के साथ-साथ उसके नेता

जेल में रहे हैं, इस बात का प्रमाण है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, जबकि आम आदमी पार्टी ने इस पर अंकुश लगाने की बजाए, उसे बढ़ाया है, चार कदम इनसे भी आगे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब और हरियाणा का आपस में रिश्ता है, इनकी एक ही छत है, संस्कार व संस्कृति भी एक ही है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में जनता के साथ जो वायदें किए गए थे उन्हें तेजी से पूरा करने का काम किया जा रहा है। बहनों की रसोई में 500 रुपए में गैस सिलिन्डर देने का काम किया गया है। किडनी के जो रोगी हैं उनकी हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ मेडिकल कॉलेजों में निशुल्क डायलिसिस भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर शत प्रतिशत फसलों को

का फूल खिलेगा, यहां से नशे की गतिविधियों में जो भी सलिप्त है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो गैंगस्टर कलचर है उसे सख्ती से खत्म किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की राजनीति में विश्वास रखते हैं और जैसे ही भाजपा की पंजाब में सरकार बनेगी, केन्द्र की जितनी भी योजनाएं हैं, यहां पर उन सभी को लागू करने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर औच्छी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस रैली में आने वाले लोगों को रोका गया, उनके वाहन रोके गए। रैली में लोगों को आने से रोकना व बसों को रोकना उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपस्थित सभी लोगों से आह्वान किया कि पंजाब को नम्बर वन का सूबा बनाने के लिए वर्ष 2027 में पंजाब में भाजपा की सरकार लाने का काम करे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा व रैली के आयोजक राजेश मिश्रा ने भी उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष लुधियाना रजनीश धीमान के साथ-साथ अन्य पदाधिकारीगण व समाज के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहें।

फर्जी जॉइनिंग करवा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री : अनुराग ढांडा



चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर पंजाब में कथित तौर पर फर्जी जॉइनिंग करवाने के आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री को कम से कम अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। ढांडा ने आरोप लगाया कि पंजाब में भाजपा के पक्ष में माहौल न बनने के कारण हरियाणा से युवाओं को लाकर पंजाब के मंचों पर पार्टी में शामिल होने का दिखावा किया जा रहा है। यह न केवल राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि वे किसे गुमराह करना चाहते हैं? एक ओर हरियाणा में युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल रहा, वहीं दूसरी ओर उन्हें राजनीतिक कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह हरियाणा के युवाओं के साथ अन्याय और पंजाब के युवाओं का

अपमान है। ढांडा ने कहा कि पंजाब के युवाओं में भाजपा के प्रति असंतोष के कई कारण हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब पंजाब बाढ़ की मार झेल रहा था, तब केंद्र सरकार ने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। किसान आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसानों की शहादत ने भी राज्य में गहरी नाराजगी पैदा की है, जिसे लोग आज तक भूलें नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि जिन युवाओं को हाल ही में पंजाब के मंच पर भाजपा में शामिल दिखाया गया, वे हरियाणा के निवासी हैं। "मुख्यमंत्री हरियाणा के, युवक हरियाणा के और कार्यक्रम पंजाब में कूयह पूरी कवायद मुख्यमंत्री की हताशा को दर्शाती है," उन्होंने कहा। आम आदमी पार्टी ने मांग की कि मुख्यमंत्री इस तरह के राजनीतिक प्रदर्शन बंद करें और अपने राज्य के युवाओं की समस्याओं के समाधान पर ध्यान दें। ढांडा ने कहा कि जनता अब जागरूक है और ऐसे किसी भी कथित फर्जीवाड़े का सच सामने आता रहेगा।

गुरदासपुर पुलिस हत्याकांड की केंद्रीय गृह मंत्रालय से हो स्वतंत्र जांच : सुखजिंदर सिंह रंधावा

गुरदासपुर। सीनियर कांग्रेस नेता एवं गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जिले में हाल ही में दो पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में सामने आए आधिकारिक बयान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय से करवाने की मांग की है, ताकि सच्चाई देश और प्रदेश की जनता के सामने लाई जा सके। रंधावा ने कहा कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और इसे किसी भी स्तर पर हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घटना में हर स्तर पर जवाबदेही तय होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सार्वजनिक

हुई फुटेज कथित 'आपसी शूटआउट' की थ्योरी पर गंभीर संदेह पैदा करती है। उपलब्ध दृश्य संकेत देते हैं कि घटना के समय दोनों अधिकारी या तो बैठे हुए थे अथवा विश्राम की स्थिति में थे। इसके अतिरिक्त, एक राइफल के बिस्तर के पीछे रखे होने की जानकारी भी सामने आई है, जिससे यह दावा संदिग्ध प्रतीत होता है कि उसी हथियार से फायरिंग की गई। रंधावा ने कहा कि यह केवल तथ्यात्मक असंगति नहीं, बल्कि एक बुनियादी विरोधाभास है। यदि अधिकारी आत्मरक्षा की स्थिति में ही नहीं थे, तो 'शूटआउट' की परिकल्पना स्वतः कमजोर पड़ जाती है।

राजस्थान के पत्रकार प्रतिनिधिमंडल ने अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट परेड का किया अवलोकन

अमृतसर। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), जयपुर द्वारा आयोजित गर्व की भावना को और प्रबल किया। पत्रकारों ने इस अवसर को भारत की चंडीगढ़, पंजाब एयर हरियाणा दौरे के अंतर्गत राजस्थान के विरिष्ठ पत्रकारों सुरक्षा व्यवस्था, सीमाओं की सतर्कता तथा जवानों के अनुशासन को समझने के प्रतिनिधिमंडल ने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित अटारी का महत्वपूर्ण अनुभव बताया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि अटारी बॉर्डर पर आयोजित रिट्रीट परेड का अवलोकन किया। इस अवसर पर बॉर्डर पर आयोजित यह रिट्रीट परेड देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता प्रतिनिधिमंडल ने देशभक्ति और अनुशासन से परिपूर्ण समारोह को देखा का सशक्त प्रतीक है। यह दौरा केंद्र सरकार की विभिन्न विकासत्मक और और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस व समर्पण की सराहना की। रिट्रीट परेड राष्ट्रीय महत्व की पहलों को समझने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, के दौरान सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों द्वारा प्रदर्शित अनुशासित जिसके अंतर्गत प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ एवं पंजाब के विभिन्न संस्थानों का मार्च, ऊर्जावान कदमताल और समन्वित प्रदर्शन किया। सभी में राष्ट्रीय भ्रमण कर रहा है।

सीट कम करने का एक छिपा हुआ एजेंडा है-सोरेन

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि परिसीमन की प्रक्रिया एक सुनियोजित 'साजिश' और 'छिपे एजेंडे' के तहत लायी जा रही है ताकि आदिवासी और दलितों के लिए आरक्षित सीटों को कम किया जा सके। सोरेन ने विधानसभा में यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता केवल राज्य और देश के विकास के बारे में बोलते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। बजट सत्र के आखिरी दिन सोरेन ने कहा, "परिसीमन की कवायद के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा है, जो है आदिवासी और दलितों के लिए आरक्षित सीटों को कम करना। पहले भी ऐसी कोशिशें की गई थीं, जिन्हें दिशमो गुरु शिबू सोरेन ने विफल कर दिया था। लेकिन

इस बार इसे पूरे देश के लिए एक सुनियोजित साजिश के तहत आगे लाया जा रहा है।" उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। उन्होंने भाजपा नेता अनिल महतो टाइगर की हत्या की निंदा की और कहा कि इस अपराध को अंजाम देने वालों को बर्खा नहीं जाएगा। सोरेन ने कहा, "घटना कल हुई, मैं इसकी निंदा करता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेताओं ने आज मृतक के परिजन से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि अपराधियों को बर्खा नहीं जाएगा।" मुख्यमंत्री के भाषण से पहले भाजपा के विधायकों ने सदन बहिर्गमन वाकआउट। भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि



उनके नेता केवल राज्य और देश के सर्वांगीण विकास के बारे में बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाया, "उनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता हथियाना है, भले ही उन्हें जनादेश न मिले। इसके पीछे

एक छिपा हुआ एजेंडा है। वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक राज्यों में उनकी सरकार हो, ताकि वे देश के वर्तमान संविधान को बदल सकें। सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने विजयी वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का

बजट पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर सामाजिक सुक्षा पर रहा है। उन्होंने कहा, "सरकार करीब 58 लाख महिलाओं को मईया सम्मान योजना का लाभ दे रही है। योजना का असर एक-दो साल

जंगली हाथियों के हमले में महिला समेत दो की मौत

सिमडेगा : झारखंड के सिमडेगा जिले में शुक्रवार को अलग-अलग घटनाओं में जंगली हाथियों के हमले में दो लोगों की मौत हो गई। एक वन अधिकारी ने यह जानकारी दी। वन अधिकारी ने बताया कि महाबुआंग पुलिस थाना अंतर्गत बुरुडगी देबाटोली गांव में शुक्रवार देर रात करीब एक बजे अपने घर के बाहर सो रहे 28 वर्षीय विकास ओहदार नामक व्यक्ति को हाथी ने कुचलकर मार डाला। सिमडेगा के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) शशांक शेखर सिंह ने बताया कि दूसरी घटना बानो थाना क्षेत्र के जामंग गांव में सुबह करीब छह बजे हुई। यहां पास के जंगल में महुआ के फूल एकत्र करने गई सिबिरया लुगुन नामक 45

वर्षीय महिला को हाथी ने हमला कर मार डाला। वन विभाग ने मृतक के परिजनों को तत्काल राहत के रूप में 10,000 रुपये प्रदान किए। अधिकारी ने बताया कि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मुआवजे की शेष राशि परिजनों को प्रदान की जाएगी। हाथी के हमले में जान गवाने वालों को झारखंड सरकार चार लाख रुपए का मुआवजा देती है।





पुलिस महानिदेशक वाई बी खुरानिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की सुरक्षा समीक्षा की

भुवनेश्वर ३१/०७ (संवाददाता): ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वाई बी खुरानिया ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि तीन अगस्त से शुरू होने वाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राज्य के तीन दिवसीय दौरे के दौरान वीवीआईपी सुरक्षा के लिए 'जल्द बुक' में तय प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ओडिशा पुलिस मुख्यालय के एक बयान में कहा गया, "डीजीपी ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित इकाइयों अति विशिष्ट व्यक्ति (वीवीआईपी) को दी जाने वाली सुरक्षा के तहत 'जल्द बुक' में तय प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

अलग-अलग विभागों के बीच सुरक्षा से जुड़े सभी कार्यों में बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं।" खुरानिया ने राष्ट्रपति की आगामी यात्रा को लेकर एक बैठक में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। इस बैठक में कई



वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिनमें निदेशक (खुफिया) आर पी कोचे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) (कानून व्यवस्था) संजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (राज्य सशस्त्र पुलिस) (एडीजीपी-एसएपी) राजेश कुमार, पुलिस आयुक्त (भुवनेश्वर-कटक) देवदत्त सिंह, पूर्व तट रेलवे (ईसीओआर) के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त (पीसीएससी) आलोक बोहरा, आईजीपी

(सीआर) सत्यजीत नाइक और पुलिस अधीक्षक (एसपी), अपराध अन्वेषण विभाग-अपराध शाखा (सीआईडी-सीबी), विवेकानंद शर्मा शामिल थे। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के अनुसार, मुर्मू तीन अगस्त की दोपहर नयी दिल्ली से एक विशेष विमान से भुवनेश्वर पहुंचेंगी और फिर सड़क मार्ग से कटक जिले के बांकी के पास स्थित जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालय जाएंगी, जहां वह संस्थान का उद्घाटन करेंगी।

रात्रि विश्राम के लिए वह भुवनेश्वर लौट आएंगी। राष्ट्रपति चार अगस्त को भुवनेश्वर से बेरहामपुर तक ट्रेन से यात्रा करेंगी और वहां से सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तसपानी जाएंगी। तसपानी में वह सनाखेमुंडी प्रखंड के अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत में स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा-अर्चना और आरती करेंगी तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगी। अधिकारियों ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की

बारिश की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए ट्रेन यात्रा का कार्यक्रम तय किया गया है। सुरक्षा तैयारियों के तहत सभी जगहों और यात्रा के मार्गों पर बम निरोधक दस्ते से जांच की सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि रेलवे पटरी की निगरानी बढ़ा दी गई है और यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले सभी समपार फाटक पर कर्मचारी तैनात रहेंगे। बयान के अनुसार प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी के लिए तैनात रेलवे कर्मचारियों की पहले ही पहचान की जा रही है और सुचारु प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए उन्हें ड्यूटी पास जारी किए जा रहे हैं। तैयारियों को मजबूत करने के लिए ड्रोन से निगरानी और जगहों व मार्गों की लगातार जांच जैसे व्यापक सुरक्षा उपाय भी किए जा रहे हैं। डीजीपी ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रपति के दौरे को सुचारु, सुरक्षित और गरिमापूर्ण बनाने के लिए पुलिस, रेलवे और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखें।

मोहन चरण माझी ने अमित शाह और अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात, मांगा सहयोग

भुवनेश्वर ३१/०७ (संवाददाता): ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान, उन्होंने राज्य में औद्योगिक सुरक्षा को मजबूत करने और रेल संपर्क का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार का समर्थन मांगा और कहा कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी बयान के मुताबिक, दिल्ली में शाह और वैष्णव के साथ अलग-अलग हुई मुलाकात में माझी ने औद्योगिक विकास, आंतरिक सुरक्षा, रेलवे बुनियादी ढांचा और लंबी अवधि की आर्थिक योजना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

बयान के अनुसार, शाह के साथ मुलाकात में माझी ने कहा कि ओडिशा विकास, प्रगति और समृद्धि की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने औद्योगिकीकरण की गति को बनाए रखने के लिए औद्योगिक सुरक्षा को मजबूत करने में केंद्र से सहयोग मांगा। बयान में कहा गया है कि माझी ने गृह मंत्री को राज्य की विकास योजनाओं, कानून-व्यवस्था की



स्थिति, आंतरिक सुरक्षा और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में भी जानकारी दी। माझी ने कहा कि ओडिशा को नक्सल-मुक्त राज्य के रूप में मान्यता मिली है, जिससे सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनुकूल माहौल बना है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 'ग्रामोदय योजना' के जरिये उन इलाकों में केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है, जो पहले वामपंथी उपवाद से प्रभावित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सक्रिय पुलिसिंग की वजह से कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है।

सीएमओ के मुताबिक, शाह ने राज्य की विकास और कल्याणकारी पहलों की सराहना

की तथा ओडिशा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए केंद्र की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, माझी ने दिल्ली में वैष्णव से भी मुलाकात की और रेलवे बुनियादी ढांचा को मजबूत करने, लंबित रेल परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और पूरे राज्य में संपर्क बेहतर बनाने पर चर्चा की

माझी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, हमारी प्राथमिकता आर्थिक विकास को गति देने के लिए क्षेत्रीय और औद्योगिक संपर्क को बेहतर बनाना है। केंद्र सरकार के लगातार सहयोग से हम एक विकसित और समृद्ध ओडिशा की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं।

मवेशी तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, 300 से ज्यादा मवेशी बचाए गए

मयूरभंज ३१/०७ (संवाददाता):उत्तरी ओडिशा में चल रहे कथित मवेशी तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई तेज हो गई है, पुलिस ने मयूरभंज से पश्चिम बंगाल में तस्करी की कोशिश के दौरान 300 से ज्यादा मवेशी बरामद किए और 11 लोगों को गिरफ्तार किया। यह ताजा कार्रवाई एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है जो शुरू में ज्योंझर में शुरू हुआ था और अब पाँच से ज्यादा जिलों में फैल गया है। तस्कर पैदल मवेशी ले जाते हुए पकड़े गए पुलिस के अनुसार, 11 आरोपियों को बारीपदा इलाके में नेशनल हाईवे 49 पर पैदल मवेशियों की तस्करी करते हुए पकड़ा गया। जानवरों को पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था, तभी बंगिरीपोसी में स्थानीय लोगों ने इस ग्रुप को रोका और पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि ये संदिग्ध भद्रक, जाजपुर और ज्योंझर जिलों के रहने वाले हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा



गिरफ्तारी तब हुई जब तस्करी नेटवर्क के पीछे के मास्टरमाइंड माने जाने वाले लोगों से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। बारीपदा और रायरंगपुर में छापे चल रहे ऑपरेशन के तहत, पुलिस ने बारीपदा में सुरोजित मोहंती के घर पर छापा मारा, जिसकी पहचान इस रैकेट में एक मुख्य साजिशकर्ता के रूप में हुई है। छापे के दौरान, लगभग 33 लाख रुपये नकद, साथ ही सोने और चांदी के गहने जप्त किए गए। रायरंगपुर के टेंटोपोसी में एक अलग ऑपरेशन में, पुलिस ने लगभग सात घरों पर छापे मारे, जो कथित तौर पर मवेशी तस्करी की गतिविधियों से जुड़े थे। चार पिकअप ट्रक और नौ मोटरसाइकिलें जप्त की गईं, जबकि छह लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। आर्थिक अपराध का एंगल जांच के दायरे में बारीपदा सदर सब-डिविज़नल पुलिस अधिकारी (स्क्वड) ने कहा कि आने वाले दिनों में छापे और ज़रूती की कार्रवाई और तेज की जाएगी। उन्होंने कहा कि रैकेट से जुड़े पाए जाने वाले लोगों पर आर्थिक अपराध की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। जांचकर्ता आरोपियों की आय के स्रोतों और संपत्ति के जमावड़े की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति कैसे हासिल की। मास्टरमाइंड की पहचान हुई, और

गिरफ्तारियों की उम्मीद पुलिस ने बताया कि तस्कर अपनी अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए लोहे की छड़ों, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री के व्यापार का बहाना बना रहे थे। जबकि गिरफ्तार किए गए 11 लोग मुख्य रूप से मवेशियों की ढुलाई में शामिल थे, जांचकर्ताओं ने नेटवर्क के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगा लिया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

ओडिशा देश के शासन सुधारों में सक्रिय भागीदार

भुवनेश्वर ३१/०७ (संवाददाता): मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि ओडिशा भारत के प्रशासनिक सुधारों के अभियान में एक सक्रिय भागीदार रहा है। यहाँ लोक सेवा भवन के कन्वेंशन सेंटर में सुशासन प्रथाओं पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि राज्य केंद्र सरकार के साथ

मिलकर प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ा रहा है। अपने मुख्य भाषण में, मुख्यमंत्री माझी ने कामाज रहित बजट से लेकर डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र तक, प्रशासनिक परिवर्तन में ओडिशा की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ओडिशा को न केवल एक मेजबान के रूप में, बल्कि उज़रदायी और पारदर्शी शासन की दिशा में भारत की यात्रा में एक सक्रिय

भागीदार के रूप में योगदान देने पर गर्व है। राज्य की डिजिटल छलांग पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री माझी ने राज्य सरकार की प्रमुख पहलों जैसे ओडिशा सचिवालय वर्कज़्लो ऑटोमेशन सिस्टम (OSWAS) और अभिनव वर्क पासबुक को पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक सहभागिता बढ़ाने के मॉडल के रूप में उद्धृत किया।

शहरों के कायाकल्प के लिए समृद्ध सहारा योजना पर विचार

भुवनेश्वर ३१/०७ (संवाददाता):मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को 4,879 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शहरों को विकास केंद्रों में बदलने हेतु समृद्ध सहारा योजना सहित 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि आवास एवं शहरी विकास विभाग की समृद्ध सहारा योजना का उद्देश्य राज्य भर में नियोजित शहरीकरण और संतुलित क्षेत्रीय विकास को

बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह योजना विकसित ओडिशा-2036 विजन का एक हिस्सा है और शहरों को आर्थिक प्रगति के इंजन में बदलने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं - नगर नियोजन और विकास केंद्रों के रूप में शहर। उन्होंने कहा कि नगर नियोजन घटक के तहत, नियोजित विकास को सक्षम बनाने के लिए अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भूमि भूखंडों को एकत्रित और पुनर्गठित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह सड़क, जल आपूर्ति, सीवेज प्रणाली और

टोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे आवश्यक शहरी बुनियादी ढांचे के प्रावधान को सुगम बनाएगा। 4,114 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ, इस पहल से भूमि और परिसंपत्ति प्रबंधन में उल्लेखनीय वृद्धि होने और सतत विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। शहरी क्षेत्रों को आर्थिक परिवर्तन के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए 765.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। यह एकीकृत आर्थिक समूहों, औद्योगिक टाउनशिप और उच्च क्षमता वाले शहरी गलियारों के विकास में सहायता करेगा।

राउरकेला ३१/०७ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) के ज्ञानार्जन एवं विकास केंद्र द्वारा 30 जुलाई, 2026 को 'उत्पादकता बढ़ाने एवं हॉट मेटल सिलिकॉन में कमी लाने' विषय पर एक दिवसीय परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट वर्कशॉप (पी.आई.डब्ल्यू.) का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ज़्लास्ट फर्नेस (बी.एफ.), स्टील मेल्टिंग शॉप (एस.एम.एस.), कोक ओवन (सी.ओ.), सिंटर प्लांट, आर.एम.एच.पी. तथा टी.आर.एम. विभागों के कार्यपालकों एवं गैर-कार्यपालकों सहित कुल 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह कार्यशाला तकनीकी ज्ञानवर्धन, अनुभवों के आदान-प्रदान तथा परिचालन दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से सामूहिक विचार-विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। कार्यक्रम का उद्घाटन आर.एस.पी. के कार्यपालक निदेशक (वर्कसट), श्री बी.आर.पलई ने किया। इस अवसर पर मुख्यस महा प्रबंधक (विजल) तथा अतिरिक्त प्रभार



कार्यपालक निदेशक (विजल), श्री आर.दासगुप्ता, मुख्य महा प्रबंधक, आर.डी.सी.आई.एस., आर.एस.पी. सेंटर, श्री एस.चट्टोपाध्याय तथा आर.एस.पी. के मुख्य महा प्रबंधक, ज़्लाचस्ति फर्नेस, श्री सुमित कुमार भी उपस्थित थे। अपने उद्घाटन संबोधन में श्री पलई ने कहा कि कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य लागत में कमी लाना है। उन्होंने प्रतिभागियों से ऐसे व्यावहारिक एवं कार्यान्वित योग्य सुझाव प्रस्तुत करने का आह्वान किया, जिनसे प्रमुख तकनीकी एवं आर्थिक मानकों में सुधार लाया जा सके। उन्होंने इस बात पर

विशेष बल दिया कि तकनीकी चर्चा को कार्ययोजनाओं में परिवर्तित किया जाए, ताकि संयंत्र के समग्र प्रदर्शन में सार्थक योगदान सुनिश्चित हो सके। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है लौह निर्माण प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने तथा ज़्लास्ट फर्नेस के प्रदर्शन में सुधार लाने पर रहा। इसके अंतर्गत उत्पादकता वृद्धि, लागत अनुकूलन तथा परिचालन अनुशासन जैसे विषयों पर संरचित तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों का उद्देश्य संयंत्र के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच व्यावहारिक अनुभवों का आदान-प्रदान

बढ़ाना तथा प्रक्रिया दक्षता एवं उत्पाद गुणवत्ता में सुधार हेतु उपयोगी सुझाव विकसित करना था। तकनीकी सत्रों की प्रारंभ में लौह निर्माण की मूलभूत अवधारणाओं एवं ज़्लास्ट फर्नेस संचालन पर विस्तृत चर्चा से हुई, जिसमें विशेषज्ञों ने हॉट मेटल की गुणवत्ता तथा भट्ठी की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले प्रमुख प्रक्रिया मानकों की विस्तार से जानकारी दी। संपूर्ण दिवस पर आयोजित तकनीकी प्रस्तुतियों में संयंत्र के प्रदर्शन में सुधार, परिचालन संबंधी बाधाओं की पहचान तथा दैनिक कार्यों में लागत-प्रभावी उपायों को

अपनाने के विभिन्न पद्धति पर विस्तार से चर्चा की गई। अपराह्न के सत्र में प्रतिभागियों के विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया, जहाँ उन्होंने विशिष्ट प्रदर्शन संबंधी चुनौतियों पर विचार-विमर्श कर उनके व्यावहारिक समाधान सुझाव दिये। इसके पश्चात प्रत्येक समूह ने समापन सत्र में अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत करते हुए उत्पादकता बढ़ाने, हॉट मेटल में सिलिकॉन की मात्रा कम करने तथा परिचालन लागत के अनुकूलन के लिए प्रभावी उपायों का प्रस्ताव रखा। इस परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट वर्कशॉप (पी.आई.डब्ल्यू.) को परिचालन उत्कृष्टता को सुदृढ़ बनाने तथा ज़्लास्ट फर्नेस प्रदर्शन प्रबंधन के प्रति साझा समझ को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में शामिल किया गया। कार्यक्रम का संचालन उप महा प्रबंधक, ज़्लास्ट फर्नेस, श्री बी.बी. के.बेहरा, के साथ सहायक महा प्रबंधक, एच.आर.-एल.एण्ड डी., सुश्री ज्योति ओरेया, तथा वरिष्ठ प्रबंधक, एच.आर.-एल.एण्ड, डी., सुश्री ज्योतिमयी राउरतिया ने किया।